कर्नाटक राज्य टी आर.सेक. एचएसजी. और यू आरबी. व अन्य

बनाम

वासावादत्ता सीमेंट व अन्य

(सिविल अपील क्रमांक 1918 / 2015)

फ़रवरी 16, 2015

[सुधांसु ज्योति मुखोपाध्याय और विक्रमजीत सेन, जे.जे.]

कर्नाटक नगर पालिका अधिनियम, 1961 धाराएं 9, 3 छोटे शहरी क्षेत्रों के गठन, उन्मूलन आदि की प्रक्रिया का अनुपालन - नगर पालिका परिषद, सेदम की मौजूदा सीमाओं में बदलाव करते हुए नगर पालिका की नगर पालिका सीमा के भीतर एक सर्वेक्षण को शामिल करने के लिए अधिसूचना जारी की गई। सेदाम - पहले प्रतिवादी द्वारा इस आधार पर चुनौती दी गई कि नोटिस को पहले प्रतिवादी कारखाने के क्षेत्र में पोस्ट किया जाना चाहिए था, जिसमें मिनी टाउनशिप है - उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को यह कहते हुए अनुमति दी कि अधिसूचना पोस्ट करने का कोई उचित अनुपालन नहीं हुआ था। अपेक्षित स्थान - अपील पर, आयोजित: अधिसूचना से प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों को विशिष्ट स्थानों पर नोटिस लगाकर पर्याप्त रूप से सूचित किया गया था - प्रथम प्रतिवादी की भूमि के अलावा, अन्य की भूमि भी उक्त अधिसूचना में दिखाई गई थी – जहां तक एक ही तारीख की दो अधिसूचनाओं का सवाल

है, पहली अधिसूचना में इसे चार स्थानों पर लगाने का निर्देश दिया गया था, और दूसरी अधिसूचना में इसे नौ स्थानों पर लगाने का निर्देश दिया गया था जो तैयार की गई थी और यदि बाद में कोई हो - राज्य ने न तो कोई दस्तावेज़ बनाया और न ही उसे उच्च न्यायालय या इस न्यायालय के समक्ष दाखिल किया - दस्तावेज़ को किसी अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर रखने के लिए बनाया गया है ताकि इसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके, यह एक गंभीर मामला है की जांच संबंधित प्राधिकारी द्वारा की जानी चाहिए – इस प्रकार, राज्य सरकार ने इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया । भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद। 243 क्यू

न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया गया :

1.1 कर्नाटक नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 9 के तहत विशिष्ट/सुविधाजनक स्थानों पर नोटिस लगाना अनिवार्य है। स्थानीय क्षेत्र के कलेक्टर कार्यालय, पंचायत कार्यालय, डी. तहसीलदार का कार्यालय, नगर पालिका कार्यालय, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड आदि सार्वजनिक स्थान हैं; जहां आम जनता द्वारा किसी न किसी कारण से आने की उम्मीद की जाती है । स्थानीय क्षेत्र को छोटा शहरी क्षेत्र घोषित करने या ऐसे किसी छोटे शहरी क्षेत्र की सीमा में बदलाव के बारे में नोटिस पोस्ट करने के लिए उन स्थानों को सुरक्षित रूप से विशिष्ट/सुविधाजनक स्थान होने की उम्मीद की जा सकती है। [पैरा 13,14] [410-सी,ई-एफ]

1.2 पहले प्रतिवादी का रुख कि नोटिस पहले प्रतिवादी की टाउनशिप के भीतर पोस्ट किया जाना चाहिए था, धारा 9 के उद्देश्य को विफल कर देगा क्योंकि अन्य प्रभावित व्यक्ति जिनकी भूमि भी उक्त अधिसूचना के दायरे में आएगी, उन्हें कोई नोटिस नहीं मिलेगा। सार्वजनिक स्थान नहीं होने के कारण प्रथम प्रतिवादी के कारखाने की सीमाओं के भीतर पोस्ट किए गए ऐसे नोटिस तक पहुंच । ऐसे मामले में, प्रत्येक व्यक्ति/प्रभावित व्यक्ति अपने जी पर इस तरह के नोटिस को पोस्ट करने का दावा करेगा भूमि जो सभी प्रभावित व्यक्तियों को व्यक्तिगत नोटिस देने के समान होगी। [पैरा 15] [410-जी- एच; 411-ए]

1.3 सभी व्यक्ति, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अधिसूचना से प्रभावित हैं, को विशिष्ट स्थानों पर दिनांक 3 अक्टूबर, 1995 की नोटिस द्वारा पर्याप्त रूप से सूचित किया गया था। यह दलील कि 28 नवंबर, 1995 की अधिसूचना द्वारा केवल प्रथम प्रतिवादी की फैक्ट्री और आवासीय क्षेत्र को जोड़ा गया था, इस तथ्य के मद्देनजर स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि प्रथम प्रतिवादी की भूमि के अलावा, अन्य की भूमि भी उक्त अधिसूचना में दिखाई गई थी। दिनांक 28 नवंबर, 1995 । [पैरा 17,18] [412-डी-एफ]

1.4 3 अक्टूबर 1995 की दो अधिसूचनाएँ हैं जिनका क्रमांक एक ही है। वस्तुतः, 3 अक्टूबर, 1995 की दोनों अधिसूचनाएँ एक ही हैं लेकिन अंतिम पैराग्राफ में पर्याप्त अंतर है जिसमें उन स्थानों का उल्लेख है जहाँ

अधिसूचना की प्रतियां पोस्ट की जानी थीं । पहली अधिसूचना जो मूल प्रतीत होती है, उसमें यह दर्शाया गया है कि नोटिस को चार स्थानों, पंचायत कार्यालय, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और शहर नगर परिषद के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाना है। दूसरी अधिसूचना से पता चलता है कि उक्त अधिसूचना को नौ स्थानों पर लगाने का निर्देश जारी किया गया है, यानी पहली अधिसूचना में उल्लिखित चार स्थानों के अलावा पांच और स्थानों पर। अतिरिक्त पांच स्थानों में प्रथम प्रतिवादी का परिसर शामिल है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 3 अक्टूबर 1995 की अधिसूचना जिसमें नौ विशिष्ट स्थानों को शामिल किया गया था, जहां इसे अधिसूचित किया जाना था, किसी अधिकारी द्वारा हरी स्याही से हस्ताक्षरित बाद में तैयार की गई थी। [पैरा 19] [412-जी-एच; 413-ए;सी-ई]

1.5 राज्य ने न तो कोई दस्तावेज़ बनाया है न ही इसे उच्च न्यायालय या इस न्यायालय के समक्ष दायर किया। यदि कोई दस्तावेज़ किसी अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर रखने के लिए बनाया गया है ताकि उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके, तो यह एक गंभीर मामला है जिसकी संबंधित प्राधिकारी द्वारा जांच की जानी आवश्यक है। प्रमुख सचिव, कर्नाटक राज्य को टीएमसी, सेदम कार्यालय से जारी अधिसूचना दिनांक 3 अक्टूबर, 1995 के संबंध में जांच करने का निर्देश दिया गया है, जिस पर मुख्य अधिकारी, सेदम द्वारा हरी स्याही से हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें

अधिसूचनाएं पोस्ट करने के लिए नौ स्थान दिखाए गए हैं। [पैरा 21] [413-जी-एच; 414-ए, सी-डी]

कलेक्टर (जिला मजिस्ट्रेट) इलाहाबाद एवं अन्य। बनाम राजा राम जयसवाल 1985 (3) एससीआर 995 (1985) 3 एससीसी 1; सैयद हसन रसूल नुमा एवं अन्य। बनाम भारत संघ एवं अन्य। 1990 डी (3) सप्ल। एससीआर 165: (1991)1 एससीसी 401; जेएंडके हाउसिंग बोर्ड और अन्य । बनाम कुँवर संजय कृष्ण कौल और अन्य । 2011 (14) एससीआर 976: (2011) 10 एससीसी 714; क्लसम आर. नाडियाडवाला बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य। (2012) 6 एससीसी 348 संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

1985 (3) एस.सी.आर. 995	संदर्भित	पैरा संख्या 9
1990 (3) सप्लण् एस.सी.आर.165	संदर्भित	पैरा संख्या 9
2011 (14) एस.सी.आर. 976	संदर्भित	पैरा संख्या 9
(2012) 6 एस.सी.सी. 348	संदर्भित	पैरा संख्या 9

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1918/2015

कर्नाटक उच्च न्यायालय, सर्किट बेंच गुलबर्गा के अपील संख्या 2999/2004(एलबी-आरईएस) में, पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 23.06.2010 से उत्पन्न ।

ए. शेनॉय अपीलकर्ताओं के लिए।

जयंत भूषण, ब्रिजेश कलप्पा, दिव्या नायर, एन. ए गणपति, अजय भार्गव, वनिता भार्गव, अरविंद रे, खेतान एंड कंपनी उत्तरदाताओं के लिए.

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय, जे. द्वारा पारित किया गया :

1. विलम्ब क्षमा किया गया। अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील अपीलकर्ता-कर्नाटक राज्य द्वारा 2004 की रिट अपील संख्या 2999 (एलबी-आरईएस) में कर्नाटक उच्च न्यायालय, गुलबर्गा की सर्किट बेंच द्वारा पारित 23 जून, 2010 के फैसले के खिलाफ दायर की गई है । आक्षेपित निर्णय के अनुसार, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने रिट अपील की अनुमति देते हुए निम्नानुसार कहा:

> "धारा 9 के प्रावधान और अदालत के समक्ष प्रस्तुत अधिसूचना पर गहन विचार करने पर, जो ऊपर निकाली गई है, यह पता चलता है कि धारा 9 में बताए गए अपेक्षित स्थानों पर अधिसूचना पोस्ट करने का कोई उचित अनुपालन नहीं है ।"

3. मामले का तथ्यात्मक मैट्रिक्स इस प्रकार है:

कर्नाटक सरकार ने शुरू में मसौदा अधिसूचना संख्या एचयूडी 14 टीएमएल 84 दिनांक 19 जून/22 जुलाई, 1986 द्वारा सर्वेक्षण संख्या को

शामिल करने के लिए टाउन म्यूनिसिपल काउंसिल (इसके बाद संक्षेप में 'काउंसिल' के रूप में संदर्भित) सेदम की मौजूदा सीमाओं को बदलने का प्रस्ताव रखा था। 630-642 शहर नगर पालिका (बाद में 'नगर पालिका' के रूप में संदर्भित) की नगरपालिका सीमा के भीतर, सेदाम उससे प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों से प्रस्ताव पर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करता है। इसके बाद कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एचयूडी 14 टीएमटी 84 दिनांक 15 अप्रैल/ 20 मई, 1987 को कर्नाटक राजपत्र में प्रकाशित किया गया। दिनांक 25 मई, 1987 को कर्नाटक नगर पालिका अधिनियम, 1961 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, परिषद, सेदम की मौजूदा सीमाओं को इसमें विस्तृत रूप से बदल दिया गया। प्रथम प्रतिवादी द्वारा बी उपरोक्त अधिसूचना के खिलाफ 1987 की एक रिट याचिका संख्या 10187 दायर की गई थी जिसे बाद में जारी अधिसूचना के मद्देनजर वापस लेने की अनुमति दी गई थी। राज्य सरकार द्वारा 28 नवम्बर, 1995 को।

28 नवंबर, 1995 की उक्त अधिसूचना द्वारा, सी को सूचित किया गया था कि 26 सितंबर, 1995 की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की उक्त अवधि के भीतर प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं मिली है, जिससे प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों से आपत्तियां आमंत्रित की जा सकें। अधिनियम की डी धारा 9 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त

शक्ति का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक के राज्यपाल ने अनुसूची 'ए' में छोटे शहरी क्षेत्र को निर्दिष्ट किया और जिसकी सीमाएँ अनुसूची 'बी' में निर्दिष्ट हैं और आगे इसे 'कहा जाने वाला' निर्दिष्ट किया। सेदम के टाउन नगर परिषद क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए:

1) अनुसूची-ए में निर्दिष्ट क्षेत्र की जनसंख्या बीस हजार से कम नहीं बल्कि पचास हजार से कम है।

2) ऐसे क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक हजार पांच सौ निवासियों से कम नहीं होना चाहिए:

3) पिछली पिछली जनगणना के वर्ष में ऐसे क्षेत्र से कर और गैर-कर स्रोतों से स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पन्न राजस्व 9,00,000/- रुपये प्रति वर्ष से कम नहीं होना चाहिए;

4) इसके अलावा गैर-कृषि गतिविधियों में रोजगार का प्रतिशत 15% से कम नहीं है कुल रोजगार.

4. पहले प्रतिवादी ने उक्त अधिसूचना को चुनौती देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय, बैंगलोर के समक्ष एक और रिट याचिका संख्या 14554/96 दायर की और इसे 19 अगस्त, 1997 को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि यह मामला किसी अन्य मामले में दिए गए निर्णय के अंतर्गत आता है। . विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश

को सुधारने के लिए प्रतिवादी द्वारा डब्ल्यूपी संख्या 14554/1996 में एक सिविल याचिका संख्या 1233/2000 दायर की गई थी। उक्त आदेश की समीक्षा करते हुए 20 अगस्त, 2001 को याचिका स्वीकार कर ली गई और रिट याचिका संख्या 14554/1996 में पारित आदेश दिनांक 19 अगस्त, 1997 को रद्द कर दिया गया और उक्त रिट याचिका को बहाल कर दिया गया। हालाँकि, पक्षों को सुनने के बाद, 24 मई, 2004 को विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि किसी क्षेत्र को मौजूदा टाउन नगरपालिका सीमा की सीमा में शामिल करने की कार्रवाई अनिवार्य रूप से एक सशर्त कानून है और इसलिए न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक है। गारंटी नहीं है.

5. उक्त आदेश के खिलाफ, प्रतिवादी ने रिट अपील संख्या 2999/2004 दायर की, जिसे डिवीजन बेंच ने 23 जून, 2010 के आक्षेपित फैसले द्वारा अनुमति दी थी।

6. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने आक्षेपित निर्णय पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस मामले में अधिनियम की धारा 9 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का काफी हद तक पालन और अनुपालन किया गया है। पहले अपीलकर्ता के निर्देशों के तहत तीसरे अपीलकर्ता ने सभी विशिष्ट स्थानों पर मौजूदा नगरपालिका सीमा के भीतर स्थानीय क्षेत्र को शामिल करने की घोषणा करते हुए नोटिस पोस्ट किया था, जिसमें 90

दिनों के भीतर जनता से आपत्ति मांगी गई थी, लेकिन निर्धारित समय के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

7. प्रथम प्रतिवादी के विद्वान वकील के अनुसार, नोटिस को छोटे शहरी क्षेत्रों में जोड़े जाने या हटाए जाने वाले क्षेत्र में पोस्ट किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में उद्घोषणा न तो पहली प्रतिवादी फैक्ट्री के क्षेत्र में पोस्ट की गई है, जो लगभग 1235.03 एकड़ का एक बड़ा क्षेत्र है, जिसमें मिनी टाउनशिप हैं और न ही किसी अन्य क्षेत्र में पोस्ट की गई है, जिसे मौजूदा छोटे शहरी क्षेत्र में शामिल करने की मांग की गई है। एकमात्र स्थान जहां इसे कथित तौर पर पोस्ट किया गया है वे चार हैं;

(1) पंचायत कार्यालय, पुरानी बाजार, सेदाम

(2) रेलवे स्टेशन, सेदम

(3) बस स्टैंड, सेदम और

(4) टाउन नगर परिषद, सेदम का नोटिस बोर्ड;

जो एक क्षेत्र में मौजूद थे और उनमें से कोई भी उस क्षेत्र में नहीं है जिसे छोटे शहरी क्षेत्र में शामिल करने की मांग की गई है।

8. इसके अलावा, पहले प्रतिवादी के विद्वान वकील के अनुसार, धारा 9 के दूसरे भाग में कहा गया है कि जब भी किसी छोटे शहरी क्षेत्र में किसी भी आबादी वाले क्षेत्र को जोड़ने या बाहर करने का प्रस्ताव किया जाता है, तो यह नगरपालिका परिषद का कर्तव्य होगा। साथ ही उद्घोषणा

की एक प्रति को किसी विशिष्ट स्थान पर पोस्ट करना, जिसका अर्थ है कि बसे हुए क्षेत्र को छोटे शहरी क्षेत्र से शामिल करना या बाहर करना। पहले प्रतिवादी का मामला यह है कि उसके पास एक टाउनशिप है जो श्रमिकों, प्रबंधन आदि के लिए आवास के साथ एक आबादी वाला क्षेत्र है और इस प्रकार नगरपालिका परिषद के लिए उक्त आबादी वाले क्षेत्र में विशिष्ट स्थानों पर उद्घोषणा पोस्ट करना अनिवार्य था, जिसकी मांग की गई थी। सामिल होना।

9. विद्वान वकील ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया

इस प्रस्ताव के लिए कि उद्घोषणा को प्रभावित क्षेत्र या संबंधित इलाके में पोस्ट किया जाना है और उद्घोषणा का उद्देश्य यह है कि प्रभावित व्यक्तियों को प्रस्तावित परिवर्तन के बारे में पता चल सके और ऐसी पोस्टिंग अनिवार्य है न कि केवल निर्देशिका।

(ए) (1985) 3 एससीसी 1, कलेक्टर (जिला मजिस्ट्रेट) इलाहाबाद और अन्य। बनाम राजा राम जयसवाल.

(बी) (1991)1 एससीसी 401, सैयद हसन रसूल नुमा और अन्य। बनाम भारत संघ एवं अन्य।

(सी) (2011) 10 एससीसी 714, जेएंडके हाउसिंग बोर्ड और अन्य वी एस। कुँवर संजय कृष्ण कौल एवं अन्य।

(डी) (2012) 6 एससीसी 348, क्लसम आर.नाडियाडवाला बनाम। महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य।

10. हमने पार्टियों द्वारा उठाए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

11. सुविधाजनक संदर्भ के लिए, कर्नाटक की धारा 9 नगर पालिका अधिनियम नीचे उद्धृत किया गया है:

"9. छोटे शहरी क्षेत्रों के गठन, उन्मूलन आदि की प्रक्रिया:

किसी भी स्थानीय क्षेत्र को छोटा शहरी क्षेत्र घोषित करने वाली किसी भी अधिसूचना के प्रकाशन से कम से कम तीस दिन पहले, या ऐसे किसी भी छोटे शहरी क्षेत्र की सीमा में बदलाव करने या यह घोषणा करने से कि स्थानीय क्षेत्र छोटा शहरी क्षेत्र नहीं रहेगा, राज्यपाल ऐसा करने को कहेंगे। आधिकारिक राजपत्र में अंग्रेजी और कन्नड़ में प्रकाशित किया जाएगा, और उक्त स्थानीय क्षेत्र में कन्नड़ में एक उद्घोषणा स्पष्ट रूप से लगाई जाएगी कि स्थानीय क्षेत्र को छोटा करने का प्रस्ताव है

शहरी क्षेत्र या छोटे शहरी क्षेत्र की सीमाओं को एक निश्चित तरीके से बदलने या यह घोषित करने के लिए कि स्थानीय क्षेत्र एक छोटा शहरी क्षेत्र नहीं रहेगा, जैसा भी मामला हो,

और उन सभी व्यक्तियों की आवश्यकता होगी जो उक्त प्रस्ताव पर कोई आपत्ति स्वीकार करते हैं। उक्त उद्घोषणा की तारीख से तीस दिनों के भीतर नगरपालिका प्रशासन के निदेशक को लिखित रूप में कारण सहित इसे प्रस्तुत करना होगा, और जब भी किसी छोटे शहरी क्षेत्र में किसी भी बसे हुए क्षेत्र को जोड़ने या बाहर करने का प्रस्ताव हो, तो यह किया जाएगा। नगर पालिका परिषद का भी कर्तव्य है कि वह ऐसे क्षेत्र की प्रतिलिपि बनाये। नगरपालिका प्रशासन के निदेशक, राज्यपाल को प्रस्तुत की गई प्रत्येक आपत्ति को उचित प्रेषण के साथ अग्रेषित करेंगे।

उपरोक्तानुसार ऐसी कोई भी अधिसूचना राज्यपाल द्वारा तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि प्रस्तुत की गई आपत्ति, यदि कोई हो, उसकी राय में अपर्याप्त या अमान्य न हो।"

धारा 9 एक शासनादेश निर्धारित करती है जिसका पालन राज्यपाल को किसी भी स्थानीय क्षेत्र को छोटा शहरी क्षेत्र घोषित करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन से पहले करना होता है; या ऐसे किसी छोटे शहरी क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन करना; या यह घोषणा करना कि एफ स्थानीय क्षेत्र एक छोटा शहरी क्षेत्र नहीं रहेगा। सबसे पहले, ऐसी अधिसूचना के

उद्देश्य/प्रस्ताव की घोषणा करते हुए एक उद्घोषणा अंग्रेजी और कन्नड़ दोनों भाषाओं में आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जानी चाहिए। दूसरे, ऐसी उद्घोषणा जी उक्त स्थानीय क्षेत्र में प्रमुख स्थानों पर 'कन्नड़ में' लगाई जानी चाहिए। तीसरा, ऐसी उद्घोषणा के लिए उन सभी व्यक्तियों की आवश्यकता होगी जिन्हें उक्त प्रस्ताव पर कोई आपत्तिहै, उन्हें ऐसी उद्घोषणा की तारीख से तीस दिनों के भीतर कारण बताते हुए प्रस्तुत करना होगा।

धारा 9 आगे बताती है कि जब भी यह हो किसी छोटे शहरी क्षेत्र में किसी भी आबादी वाले क्षेत्र को जोड़ने या बाहर करने का प्रस्ताव है, तो यह नगरपालिका परिषद का कर्तव्य होगा कि वह ऐसी उद्घोषणा की एक प्रति ऐसे क्षेत्र में विशिष्ट स्थानों पर लगाए। यहां प्रयुक्त वाक्यांश "ऐसे क्षेत्र" का अर्थ उस बसे हुए क्षेत्र से है जिसे छोटे शहरी क्षेत्र में जोड़ने या बाहर करने का प्रस्ताव है।

12. अधिनियम की धारा 9 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 243Q के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए जो इस प्रकार है:

"243Q नगर पालिकाओं का गठन:

(1) प्रत्येक राज्य में इसका गठन किया जाएगा, -

(ए) एक संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो), यानी ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में संक्रमण वाला क्षेत्र;

(बी) एक छोटे शहरी क्षेत्र के लिए एक नगर परिषद; और

(सी) इस भाग के प्रावधानों के अनुसार एक बड़े शहरी क्षेत्र के लिए एक नगर निगम:

बशर्ते कि इस खंड के तहत नगर पालिका का गठन ऐसे शहरी क्षेत्र या उसके किसी हिस्से में नहीं किया जा सकता है, जैसा कि राज्यपाल कर सकते हैं, क्षेत्र के आकार और उस क्षेत्र में किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा प्रदान की जाने वाली या प्रदान की जाने वाली नगरपालिका सेवाओं को ध्यान में रखते हुए और ऐसे अन्य कारक जिन्हें वह उचित समझे, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा एक औद्योगिक टाउनशिप निर्दिष्ट करें।

(2) इस अनुच्छेद में, 'एक संक्रमणकालीन क्षेत्र', 'एक छोटा शहरी क्षेत्र' या 'एक बड़ा शहरी क्षेत्र' का अर्थ ऐसे क्षेत्र से है जिसे राज्यपाल, क्षेत्र की जनसंख्या, जनसंख्या के घनत्व को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं।

उसमें, स्थानीय आर्थिक महत्व के लिए राजस्व सामान्य या ऐसे अन्य कारक जो उचित समझे जाएं, सार्वजनिक अधिसूचना या इस भाग के उद्देश्यों द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं।"

13. धारा 9 का प्रावधान कुछ हद तक भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के समान है, जिसके तहत विशिष्ट/सुविधाजनक स्थानों पर नोटिस लगाना अनिवार्य है।

यदि पहले प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा दिए गए तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो उस स्थिति में प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति जिसकी भूमि को छोटेशहरी क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन के उद्देश्य से शामिल करने की मांग की गई है, यह दावा करेगा कि डी को इस तरह का नोटिस दिया जाना चाहिए। उसकी भूमि पर तैनात किया गया।

14. स्थानीय क्षेत्र के कलेक्टर कार्यालय, पंचायत कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, नगर पालिका कार्यालय, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड आदि ई सार्वजनिक स्थान हैं; जहां आम जनता द्वारा किसी न किसी कारण से आने की उम्मीद की जाती है। स्थानीय क्षेत्र को छोटा शहरी क्षेत्र घोषित करने या ऐसे किसी भी छोटे शहरी क्षेत्र की सीमा में बदलाव के बारे में नोटिस पोस्ट करने के लिए उन स्थानों से सुरक्षित रूप से विशिष्ट/सुविधाजनकस्थान होने की उम्मीद की जा सकती है, जैसा कि भूमि अधिग्रहण के मामले में किया जाता है।

15. यदि पहले प्रतिवादी के रुख को स्वीकार कर लिया जाए कि नोटिस को पहले प्रतिवादी की जी टाउनशिप के भीतर पोस्ट किया जाना चाहिए था, तो यह अधिनियम की धारा 9 के उद्देश्य को विफल कर देगा क्योंकि अन्य प्रभावित व्यक्ति जिनकी भूमि भी दायरे में आएगी। उक्त अधिसूचना में प्रथम प्रतिवादी के कारखाने की एच सीमाओं के भीतर पोस्ट किए गए ऐसे नोटिस तक कोई पहुंच नहीं हो सकती है, नहीं होने के नाते

एक सार्वजनिक स्थान. ऐसे मामले में, प्रत्येक व्यक्ति/ प्रभावित व्यक्ति अपनी भूमि पर ऐसे नोटिस लगाने का दावा करेगा जो सभी प्रभावित व्यक्तियों को व्यक्तिगत नोटिस देने के समान होगा।

16. 3 अक्टूबर, 1995 की अधिसूचना चार प्रमुख स्थानों पर पोस्ट की गई थी, जिसका अंग्रेजी संस्करण इस प्रकार है:

"नंबर टीएमसी;95-96 टीएमसी के कार्यालय सेदाम, दिनांक 3.10.1995

अधिसूचना

विषयः सरकार का प्रकाशन। परिपत्र

संदर्भः सरकार परिपत्र, क्रमांकः एनईः 407: एमएलआरः 95, बैंगलोर, दिनांक 26.09.1995

उपरोक्त विषय के संदर्भ में, टाउन नगरपालिका क्षेत्र की जनता को सूचित किया जाता है कि संदर्भ में बताए गए परिपत्र के अनुसार, नगरपालिका क्षेत्र का विस्तार करने के लिए सेडम टाउन नगर पालिकाओं की सीमाओं को बदलने का प्रस्ताव है । यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रस्ताव पर आपत्ति हो तो वह 30 दिन के भीतर अपनी लिखित आपत्ति दर्ज करा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र को इस अधिसूचना द्वारा इसकी सूचना दी गई है।

एस.डी.,

मुख्य अधिकारी

सेदम"

यह निर्देशित किया जाता है कि अधिसूचना की प्रति निम्नलिखित स्थानों पर पोस्ट की जानी चाहिए:

i) पंचायत कार्यालय, पुराना बाजार, सेदाम

ii) रेलवे स्टेशन, सेदम

iii) बस स्टैंड, सेदम

iv) नगर पालिका परिषद का नोटिस बोर्ड, सेदम ।"

17. प्रथम प्रतिवादी के विद्वान वकील ने स्वीकार किया कि प्रथम सी प्रतिवादी का पंचायत कार्यालय पुराना बाजार, सेदम में है, निकटतम रेलवे स्टेशन सेदम में है और प्रथम प्रतिवादी के कर्मचारियों के लिए बस स्टैंड सेदम में है। यह इंगित करता है कि सभी व्यक्ति, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अधिसूचना से प्रभावित थे, उन्हें उपर्युक्त विशिष्ट स्थानों पर दिनांक 3 अक्टूबर, 1995 को पोस्ट किए गए नोटिस द्वारा पर्याप्त रूप से सूचित किया गया था।

18. पहले प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने अगली दलील दी कि 28 नवंबर, 1995 की अधिसूचना द्वारा पहले प्रतिवादी का केवल कारखाना और आवासीय ई क्षेत्र जोड़ा गया था, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते

हुए इस तरह के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि पहले प्रतिवादी की भूमि के अलावा प्रतिवादी, अन्य की भूमि भी उक्त अधिसूचना दिनांक 28 नवंबर, 1995 में दिखाई गई थी।

19. हालाँकि, मूल रिकॉर्ड के अवलोकन पर, हम 3 अक्टूबर, 1995 की दो अधिसूचनाएँ खोजें, दोनों की संख्या समान है, जो रिकॉर्ड में हैं। वस्तुतः, 3 अक्टूबर, 1995 की दोनों जी अधिसूचनाएं समान हैं लेकिन अंतिम पैराग्राफ में पर्याप्त अंतर है जिसमें उन स्थानों का उल्लेख है जहां अधिसूचना की प्रतियां पोस्ट की जानी थीं।

3 अक्टूबर 1995 की पहली अधिसूचना में, जो मूल प्रतीत होती है, यह दिखाया गया है कि नोटिस चार स्थानों पर चिपकाया जाना है, अर्थात् (i) पंचायत कार्यालय, पुराना बाजार, सेदाम; (ii) रेलवे स्टेशन, सेदम; (iii) बस स्टैंड, सेदम और (iv) नगर नगर परिषद, सेदम का नोटिस बोर्ड। यह एक पुराना कागज है, जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए लेमिनेट किया गया है कि यह क्षतिग्रस्त न हो और इसके पीछे अंगूठे के निशान के अलावा, विभिन्न व्यक्तियों से हस्ताक्षर भी लिए गए हैं ताकि यह दिखाया जा सके कि अधिसूचना उन गवाहों की उपस्थिति में पोस्ट की गई थी।3 अक्टूबर, 1995 की अन्य अधिसूचना से पता चलता है कि उक्त अधिसूचना को नौ स्थानों पर, यानी पहली अधिसूचना में उल्लिखित चार स्थानों के अलावा पांच और स्थानों पर लगाने का निर्देश जारी किया गया है।

अतिरिक्त पांच स्थानों में प्रथम प्रतिवादी का परिसर शामिल है। दूसरी अधिसूचना पर किसी अन्य अधिकारी द्वारा हरी स्याही से हस्ताक्षर किये गये हैं। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 3 अक्टूबर 1995 की अधिसूचना जिसमें नौ विशिष्ट स्थान शामिल थे, जहां इसे अधिसूचित किया जाना था, किसी अधिकारी द्वारा हरी स्याही से हस्ताक्षरित बाद में तैयार की गई है।

20. प्रथम प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने न्यायालय से संबंधित अधिकारी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने और अपील को खारिज करने का अनुरोध किया क्योंकि दस्तावेज़ न्यायालय को गुमराह करने के लिए बनाया गया है।

21. अपील कर्नाटक राज्य द्वारा प्रस्तुत की गई है। राज्य ने न तो कोई दस्तावेज़ बनाया है और न ही उसे उच्च न्यायालय या इस न्यायालय के समक्ष दायर किया है। यदि कोई दस्तावेज किसी अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर रखने के लिए बनाया गया है ताकि उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके, तो यह एक गंभीर मामला है जिसका होना आवश्यक है। संबंधित प्राधिकारी द्वारा जांच की गई। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक विस्तृत जांच की आवश्यकता है, हमें राज्य सरकार को मामले की जांच करने का निर्देश देना और यदि आवश्यक हो, तो उन कथित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना अधिक व्यवहार्य लगता है,

जिन्होंने नाम वाला दस्तावेज़ बी बनाया होगा। 3 अक्टूबर, 1995 की तथाकथित अधिसूचना में नौ प्रमुख स्थानों पर मुख्य अधिकारी, सेदम द्वारा हरी स्याही से हस्ताक्षर किए गए।

कर्नाटक राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि वे कार्यालय टीएमसी, सेदम से जारी अधिसूचना संख्या टीएमसी:एसईडीएएम:95-96 दिनांक 3 अक्टूबर, 1995 के संबंध में जांच करें, जिस पर मुख्य अधिकारी, सेडम द्वारा हरी स्याही से हस्ताक्षर किए गए हैं। सूचनाएं पोस्ट करने के लिए नौ स्थान दिखाए गए हैं। यदि यह बाद में बनाया गया दस्तावेज़ डी पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जाली दस्तावेज़ बनाने के लिए इस आशय की प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। विभागीय कार्यवाही भी शुरू की जाए और उचित कार्रवाई की जाए।

22. उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ अपील स्वीकार की जाती है।

अपील की अनुमति.

यह अनुवाद आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से न्यायिक अधिकारी श्री बुलाकी दास व्यास, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है। अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।